श्री उपसभापति: माननीय सदस्या, कृपया approved text ही पढ़ें। केवल approved text ही रिकॉर्ड में जाएगा।

Demand to give financial help to BSNL and MTNL for their revival

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, बीएसएनएल और एमटीएनएल, जिन्हें भारतीय संचार तंत्र की लाइफलाइन कहते थे, आज वे स्वयं दम तोड़ रहे हैं। दोनों पीएसयूज़, आज लगभग 18,000 करोड़ रुपए के घाटे में दबे हैं। दोनों संस्थानों का राजस्व घट रहा है, जिससे स्टाफ लागत उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। बीएसएनएल की स्टाफ लागत, जो 2016-17 में 50 प्रतिशत थी, अब 77 प्रतिशत है। एमटीएनएल की स्टाफ लागत जो 2016-17 में 75 प्रतिशत थी, अब 87 प्रतिशत हो गई है। आज डिजिटल संचार जीवन का पर्याय बन गया है। संचार कम्पनियों में विकास की आंधी चल रही है, मगर दोनों पीएसयूज़ खराब संचार सेवा और अक्षम प्रबंधन के कारण जीवन के अंतिम कगार पर हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन कम्पनियों के स्टाफ की सेवानिवृत्ति आयु घटाकर और आकर्षक वीआरएस देकर, इन्हें अनावश्यक स्टाफ-भार से बचाया जा सकता है, परन्तु ध्यान रहे कि कहीं सक्षम अधिकारी बाहर न चले जाएं और अक्षम लोग कम्पनी को डुबोने के लिए वहीं न बने रहें।

किसी भी प्रतिष्ठान में अच्छे लोग सौभाग्य लाते हैं, जबकि नकारा कर्मचारी और अधिकारी प्रतिष्ठान के लिए दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। अत: इन दोनों प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि समर्पित एवं इनोवेटिव तकनीकी अधिकारियों के साथ ही कुशल प्रबंधकों को इन्हें पुनर्जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। दोनों ही प्रतिष्ठानों के अर्थतंत्र को आर्थिक सहयोग दिए जाने की भी आवश्यकता है, परन्तु आर्थिक सहयोग का सदुपयोग केवल सक्षम प्रबंधन से ही संभव है, ऐसा मेरा विश्वास है, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: आपने जो भी शब्द अंत में, पहले या बीच में बदला, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। प्रो. मनोज कुमार झा। उपस्थित नहीं हैं। श्री मो. नदीमुल हक। उपस्थित नहीं हैं। श्रीमती छाया वर्मा।

Demand to immediately appoint teaching faculty in Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, according to the standards fixed

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, अभी कुछ माह पहले छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय में तकरीबन छ: गुना फीस बढ़ोतरी की गई थी, पर अत्यंत चिंता की बात है कि इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, सह-प्राध्यापक, सहायक प्रोफेसर के तकरीबन आधे से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, जिससे विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रोफेसरों की अनुपलब्धता के कारण विद्यार्थी आधा-अधूरा अध्ययन कर पा रहे हैं, जिससे प्रतियोगिताओं में सफलता पाने में उन्हें आगे चल कर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस संस्थान में पर्याप्त

[श्रीमती छाया वर्मा]

प्रोफेसर, सह-अध्यापक न हों, वहां के विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य प्रभावित होना लाजिमी है। अत्यधिक फीस बढ़ोतरी के बाद स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रोफेसर, सह-अध्यापक का न होना नितांत चिंता की बात है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों का अध्ययन उच्च गुणवत्तायुक्त हो, इसके लिए कई सुझाव विशेषज्ञों द्वारा रखे गए हैं, पर उन सुझावों का यदि पालन नहीं होगा, तो शिक्षा गुणवत्तायुक्त कैसे होगी?

सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर में स्थित गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय में तय मानकों के अनुरूप प्रोफेसर, सह-प्राध्यापक, सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों पर अविलम्ब नियुक्ति करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य प्रभावित न हो, धन्यवाद।

Demand to encourage organic farming in India

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, हजारों साल से अपने देश में मनुष्य के स्वास्थ्य व प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए खेती की जाती थी। जिसके कारण जैविक-अजैविक पदार्थों के मध्य तारतम्य बना रहता था, परंतु वर्तमान समय में कृषि में रासायनिक खादों व कीटनाशकों के अनाप-शनाप उपयोग ने इस चक्र को तहस-नहस कर दिया है। परिणामत: माटी की उर्वरा शक्ति कम हुई, साथ ही मनुष्य व पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

मान्यवर, सिक्किम दुनिया का प्रथम राज्य है, जिसने सालों की मेहनत के बाद अपनी 75 हजार एकड़ कृषि भूमि को पूरी तरह से जैविक खेती में बदल दिया है। सिक्किम सरकार ने जनता को रासायनिक खादों व कीटनाशकों के दुष्पारिणामों के प्रति जागरुक किया। रासायनिक खादों के भंडारण व प्रयोग को कानून बना कर प्रतिबंधित किया व रासायनिक खादों पर सरकारी अनुदान समाप्त कर दिया। वहीं स्कूली बच्चों को रासायनिक खादों व कीटनाशकों के प्रयोग किए बिना जैविक खेती के फायदों को बताने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में एक विषय के रूप में शामिल किया।

मान्यवर, मैं सरकार से इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए निम्नलिखित मांग करता हूं:-

(क) सिक्किम को आदर्श मान कर रासायनिक खादों व कीटनाशकों के उत्पादन व भंडारण को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने व जैविक खेती को पूरे देश में विकसित करने हेतु सरकार एक स्पष्ट नीति बनाए।

(ख) दूसरे, सिक्किम की तर्ज पर जैविक खेती को देश के विद्यालयों में एक विषय के रूप में पाठ्यक्रमों में शामिल करें ताकि जैविक खेती के प्रति बच्चों में बचपन से ही सकारात्मक विचार पैदा हो सके।